नंदिग्राम टाईम्स

Saturday 6th December 2025 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 220 | ● पृष्ठ 04 | ● मूल्य - 2 रूपए | ● www.nandigramtimes.com

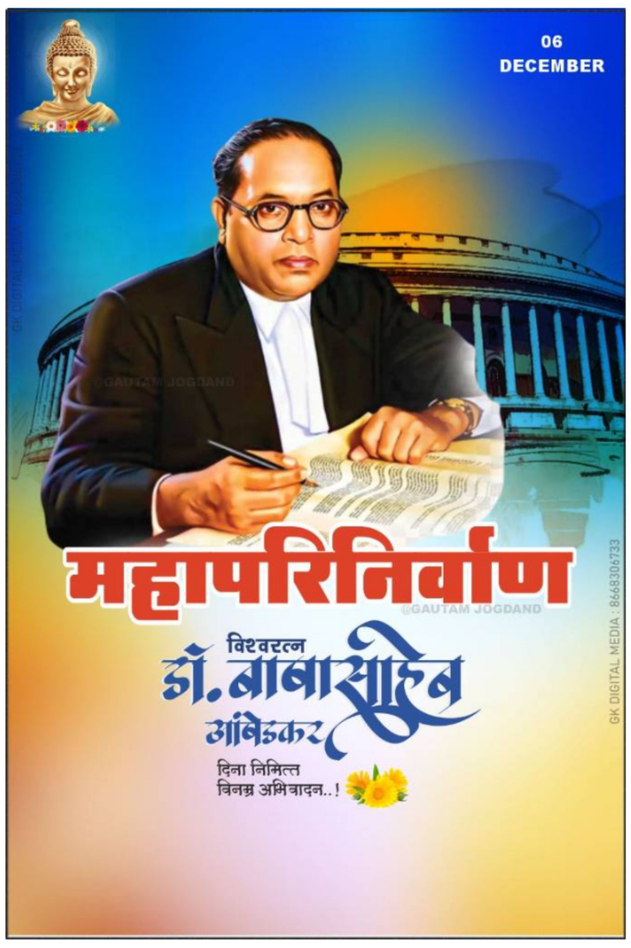

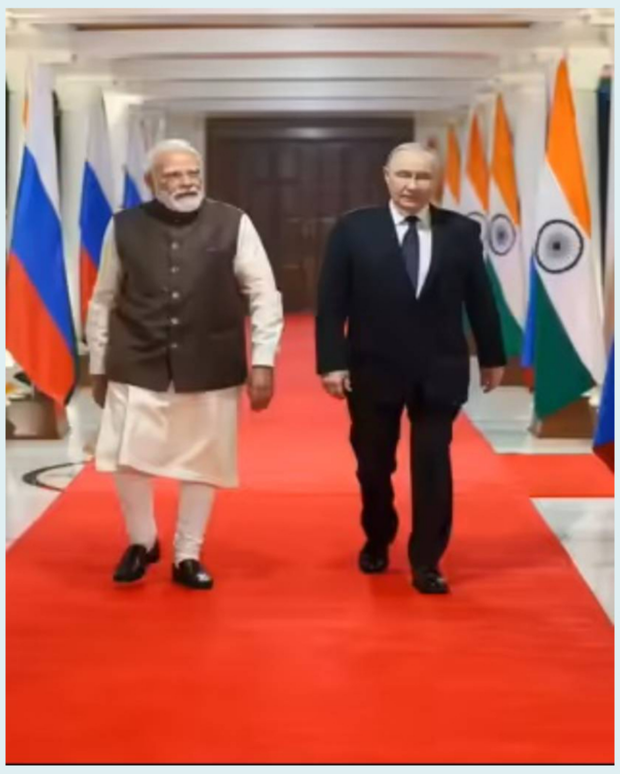

भारत ने रूसियों के लिए 30 दिन का मुफ़्त ई-टूरिस्ट वीजा जारी, मोदी–पुतिन की मेज़बानी में ऐलान

नई दिल्ली, 5 दिसंबर 2025 — रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान, भारत सरकार ने रूसी नागरिकों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। नरेंद्र मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि रूसियों को 30 दिनों का मुफ्त ई-टूरिस्ट वीजा (e-visa) और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा, “हम बहुत जल्द रूसी नागरिकों के लिए ई-टूरिस्ट वीजा व ग्रुप वीजा सेवाएं शुरू करेंगे — ये पूरी प्रक्रिया 30 दिन में पूरी होगी और निःशुल्क होगी।”

इस कदम को दोनों देशों के बीच बढ़ते सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस पहल के तहत पर्यटकों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और कलाकारों के बीच नागरिक संपर्क को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है।

साथ ही, वार्ता में एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Economic Cooperation Agreement till 2030) पर भी सहमति हुई है, जिससे व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, और तकनीकी सहयोग समेत कई क्षेत्रों में सहयोग व विस्तार की राह खुलेगी।

दोनों नेताओं ने कहा कि इस पहल से द्विपक्षीय मित्रता, पारस्परिक भरोसा और “लोग-से-लोग” संपर्कों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह कदम दोनों देशों के बीच सामूहिक विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

ELECTION NEWS | जनता का फैसला अभी सील! —21 दिसंबर को ही खुलेगा जनादेश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: महाराष्ट्र नगरपालिका-नगर पंचायत चुनावों की मतगणना अब 21 दिसंबर को ही

मुंबई | महाराष्ट्र की नगरपालिका और नगर-पंचायत चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में विभिन्न चरणों में हुए इन निकाय चुनावों की मतगणना 21 दिसंबर को ही की जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) को यह भी आदेशित किया है कि सभी निकाय चुनावों की प्रक्रिया 31 जनवरी, 2026 तक पूरी कर लेना अनिवार्य है।

गौरतलब है कि इन निकायों के चुनाव दो अलग-अलग तिथियों — 2 दिसंबर और 20 दिसंबर — को आयोजित हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला:

पहले चरण के मतदान के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि यदि आंशिक परिणाम घोषित किए गए तो दूसरे चरण पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण Bombay High Court की नागपुर खंडपीठ ने आदेश दिया था कि सभी निकायों के परिणाम एक साथ घोषित किए जाएँ, ताकि चुनावी माहौल पारदर्शी एवं निष्पक्ष बना रहे।

आज सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने हाई कोर्ट के इस आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि अलग-अलग चरणों के परिणाम अलग-अलग तारीखों पर घोषित करने से चुनावी संतुलन प्रभावित हो सकता है और इससे प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। इसलिए अब राज्य में नगरपालिका और नगर-पंचायत दोनों ही स्तरों के सभी चुनाव परिणाम एक साथ, 21 दिसंबर को घोषित किए जाएँगे।

इस फैसले का व्यापक असर राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं तीनों पर होगा। राजनीतिक दल अब अपने गणित और रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए 21 दिसंबर का इंतज़ार करेंगे। प्रत्याशी, जो मतदान के बाद से ही परिणामों की प्रतीक्षा में हैं, अब आश्वस्त हैं कि पूरी प्रक्रिया एक साथ और निष्पक्ष ढंग से होने जा रही है। वहीं, मतदाताओं के लिए भी यह फैसला लोकतांत्रिक पारदर्शिता को मजबूत करने वाला है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार की संभावित भ्रम की स्थिति को दूर किया जा सकेगा।

चुनावी सामग्री जैसे ईवीएम, मतपेटियाँ और दस्तावेज़ सुरक्षित रूप से संरक्षित रखे जाएंगे। 21 दिसंबर को पूरे राज्य में एकसाथ मतगणना के बाद अंतिम नतीजे घोषित किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश ने चुनावी प्रक्रिया में स्पष्टता ला दी है और अब सभी की नज़रें 21 दिसंबर की मतगणना पर टिकी हैं, जो महाराष्ट्र में स्थानीय शासन की तस्वीर तय करेगी।

महापरिनिर्वाण दिवस: दादर–चैत्यभूमी के आसपास 5 से 7 दिसंबर तक बड़े ट्रैफिक बदलाव लागू

मुंबई — डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर चैत्यभूमी, दादर में लाखों अनुयायियों के आगमन की संभावना को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 5 से 7 दिसंबर तक विशेष ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दादर व शिवाजी पार्क क्षेत्र के कई प्रमुख मार्गों को बंद या डायवर्ट किया गया है।

स्वातंत्र्यवीर सावरकर मार्ग (S.V.S. रोड), रानाडे रोड, एस. के. बोले रोड, एम. बी. राऊत मार्ग, जांभेकर महाराज रोड और केलुस्कर रोड सहित कई रस्तों पर आवाजाही सीमित रहेगी। एस. के. बोले रोड को एकतरफा मार्ग बनाया गया है—सिद्धिविनायक मंदिर मोड़ से पोर्तुगीज चर्च जंक्शन की ओर ही वाहन जा सकेंगे, विपरीत दिशा बंद रहेगी। इसके अलावा, महिम जंक्शन,

महापरिनिर्वाण दिवस: दादर–चैत्यभूमी

हिन्दुजा अस्पताल, एल. जे. रोड, गोखले रोड, सेनापति बापट मार्ग और तिलक ब्रिज क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह रोक दिया गया है।

भीड़ को ध्यान में रखते हुए कई मार्गों पर नो-पार्किंग ज़ोन लागू किए गए हैं। रानाडे रोड, बोले रोड, एम. बी. राऊत मार्ग, केलुस्कर रोड और आसपास के कई छोटे मार्गों पर किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। बीएमसी और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी शौचालय, जल आपूर्ति, प्राथमिक चिकित्सा, बैरिकेडिंग और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था की है। अधिकारियों ने बताया कि इन कदमों का उद्देश्य भीड़ प्रबंधन को सुचारू बनाना और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित रखना है।

ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन तीन दिनों में दादर और चैत्यभूमी की ओर जाने से बचें। आवश्यक होने पर सार्वजनिक परिवहन—विशेषकर लोकल ट्रेन और बस—का उपयोग करें और यात्रा पहले से प्लान करें। ये सभी प्रतिबंध 7 दिसंबर की रात तक प्रभावी रहेंगे।

हाईकोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की याचिका खारिज की

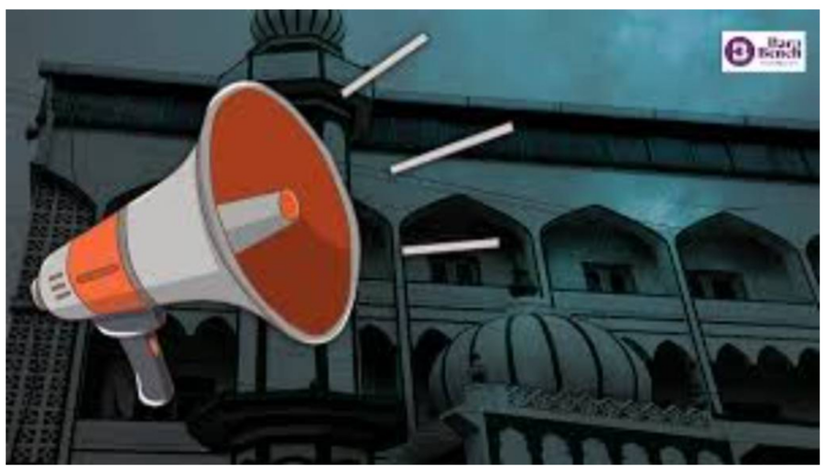

संवाददाता |

नागपुर, 5 दिसंबर 2025 — Bombay High Court की नागपुर बेंच ने Masjid A. Gousiya, गोंदिया की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की इजाज़त दी जाने की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी धर्म में लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रार्थना को अनिवार्य नहीं बताया गया है।

हाई-कोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता पक्ष ने कोई ऐसा धार्मिक या कानूनी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो सके कि धार्मिक अनुष्ठानों में ध्वनि-वर्धक यंत्रों का उपयोग मौलिक या अनिवार्य अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी नागरिक को अनचाही आवाज सुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आवाज बढ़ाने वाले यंत्रों के उपयोग से सार्वजनिक शांति और स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं। अदालत ने ध्वनि प्रदूषण को गंभीर समस्या बताया।

नांदेड़ | जि.प. दलितवस्ती निधि वितरण में अनियमितता!

वंचित बस्तियों को दरकिनार कर 19.89 करोड़ की मंजूरी

● Reporter Name

नांदेड़ : जिला परिषद समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध वस्ती विकास योजना के तहत निधि वितरण में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। विभाग ने 19 करोड़ 89 लाख 49 हजार रुपये की लागत वाले 359 विकास कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी है, लेकिन इस प्रक्रिया में वंचित बस्तियों के प्राथमिकता क्रम की अनदेखी की गई है।

इस योजना के लिए 2025–26 में 60 करोड़ 75 लाख रुपये का नियतव्यय मंजूर है। जिला परिषद के प्रशासक ने उपलब्ध निधि के आधार पर वस्ती और कार्यों का चयन किया था। उसके अनुरूप अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पहले 31 अक्टूबर को 27.74 करोड़ के 459 कार्यों को मंजूरी दी और फिर 20 नवंबर को 19.89 करोड़ के अतिरिक्त 359 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की। आरोप यह है कि इन मंजूरियों से पहले पंचायत समितियों से प्रस्ताव ही नहीं मंगाए गए,

19.89 करोड़ की मंजूरी

न ही ग्राम पंचायतों के औपचारिक ठराव समाज कल्याण विभाग तक पहुंचे थे। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर मंजूरियां देने से प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं।

इस प्रकरण के बाद जिले में चर्चा तेज है कि क्या समाज कल्याण विभाग और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच आर्थिक साटेलोटे का मामला तो नहीं? अब इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदारी निश्चित कर जांच की मांग बढ़ रही है।

नीतियों की दिशा और भविष्य की परीक्षा: महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था एक निर्णायक मोड़ पर

संपादकीय |

महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहाँ संयम, संवाद और दूरदृष्टि—तीनों की परख हो रही है। 5 दिसंबर को राज्यभर में स्कूलों के बंद रहने की घटना ने स्पष्ट संकेत दिया है कि नीतिगत बदलावों को लेकर शिक्षक समुदाय में असुरक्षा बढ़ी है और सरकार के साथ संवाद का पुल कमजोर पड़ चुका है। 6 दिसंबर के इस संस्करण में हम इस मुद्दे को सिर्फ विवाद नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य के रूप में देखते हैं।

संच मान्यता नीति: इरादा सही, लागू करना कठिन

सरकार द्वारा प्रस्तुत संच मान्यता नीति (Group Accreditation) का उद्देश्य स्कूलों के संचालन और गुणवत्ता को अधिक संगठित और पेशेवर बनाना है। यह सोच आधुनिक शिक्षा मॉडल के अनुकूल जरूर है, लेकिन इसे लागू करते समय जमीनी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दिया गया।

ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ एक शिक्षक और एक कमरे पर पूरा स्कूल चलता है, वहाँ समूह-आधारित मान्यता न तो व्यावहारिक है और न त्वरित रूप से लागू की जा सकती है। शिक्षक संगठनों द्वारा जताई गई यह चिंता तथ्यात्मक है कि ऐसे अचानक बदलाव से हजारों छोटे स्कूल अस्तित्वहीन हो सकते हैं।

TET अनिवार्यता: योग्यता बनाम स्थिरता का प्रश्न

शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य होना स्वाभाविक है। लेकिन दशकों से सेवा कर रहे शिक्षकों के लिए अचानक यह परीक्षा नौकरी की शर्त बन जाए, यह व्यवस्था भी संतुलित नहीं मानी जा सकती।

नीति का उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन शिक्षक समुदाय का तर्क भी उतना ही मजबूत है कि स्थिर सेवाकाल के बाद ऐसी परीक्षा थोपना उनकी सुरक्षा और सम्मान दोनों को चुनौती देता है।

सरकार की चेतावनी और बढ़ती दूरी

शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बंद करने वाले संस्थानों पर एक दिन का वेतन काटने की चेतावनी देना अनुशासन का कदम माना जा सकता है, पर इससे यह भी संदेश गया कि संवाद की गुंजाइश कम हो रही है।
नीतियाँ आदेश से नहीं, विश्वास से लागू होती हैं—यह सिद्धांत प्रशासन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल—बच्चों का हक़ कौन देखेगा?

इन विवादों के बीच सबसे अधिक प्रभावित वे लाखों बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई एक बार फिर ठहर गई। नीतिगत बहस का सबसे बड़ा मूल्य विद्यार्थी चुकाते हैं—और यही चिंता का असली कारण है।

प्रशासनिक सुधारों की पहल: एक सकारात्मक कदम

राजस्व विभाग में सात विशेष सतर्कता दलों का गठन राज्य सरकार की सकारात्मक पहल है। यदि यह कदम ईमानदारी से लागू किया गया, तो भूमि एवं राजस्व से जुड़ी शिकायतों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
परंतु यह भी सच है कि सुधारों की सफलता उसके दिखने वाले परिणामों पर निर्भर करेगी, न कि केवल घोषणाओं पर।

निष्कर्ष: महाराष्ट्र को अभी टकराव नहीं, संवाद चाहिए

शिक्षा और प्रशासन—दोनों राज्य की रीढ़ हैं। इनमें सुधारों की आवश्यकता निर्विवाद है, पर सुधार तभी सार्थक होते हैं जब वे जमीन से जुड़े हों और संबंधित पक्षों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ें।

6 दिसंबर को यह साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र को इस समय शक्ति-प्रदर्शन की नहीं, बल्कि संतुलन, बातचीत और जिम्मेदारी की आवश्यकता है।
यदि सरकार और शिक्षक संगठन मिलकर समाधान की ओर बढ़ते हैं, तो यह संकट राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए सुधार का अवसर भी बन सकता है।

IndiGo | **IndiGo Flight Cancellations:**

एक हजार से ज्यादा फ्लाइट कैंसल पर Sorry... नियमों को लेकर बड़ा फैसला, अब आगे क्या?

● Reporter Name

नई दिल्ली: जिस नियम को लागू करने की वजह से इंडिगो एयरलाइंस का सारा सिस्टम बैठ गया और देशभर के हवाई अड्डों में अफरातफरी मच गई, शुक्रवार को उसे टालने का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद माना जा रहा है कि अगले तीन दिन में हालात थोड़ा सुधर सकते हैं। शुक्रवार को इंडिगो ने हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी, जो अब तक का रिकॉर्ड है। देशभर से यात्रियों की परेशान की ऐसी तस्वीरें आईं कि हंगामा मच गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने जांच के आदेश दिए हैं। इंडिगो ने सॉरी कहा है और रिफंड करने की बात की है। लेकिन, आम लोग सकते में हैं। उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बाकी एयरलाइंस ने किराये बढ़ा दिए। घरेलू किराये लंदन, न्यूयॉर्क की उड़ानों से ज्यादा महंगे हो गए।

शुक्रवार को हालात इतने बिगड़े कि दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट से इंडिगो ने पांच दिसंबर की रात 12 बजे तक की सारी फ्लाइट कैंसल कर दी। मुंबई एयरपोर्ट पर शाम 6 बजे तक फ्लाइट कैंसल की गई। इस सब की जानकारी पहले से यात्रियों को नहीं दी गई। दिल्ली के टी-1 पर बच्चे और बड़े कुर्सियां न मिलने पर नीचे फर्श पर ही बैठने को मजबूर हो गए। इंडिगो के सीईओ पीटर एलबर्स ने इसके लिए सभी से सॉरी बोलते हुए वीडियो संदेश में कहा कि हजार से अधिक फ्लाइट कैंसल हुईं, जो इंडिगो का अभी तक का सबसे बड़ा कैंसिलेशन है।

नियम 10 फरवरी तक टले
DGCA ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट के अपने नए नियम को 10 फरवरी तक टाल दिया। इसमें पायलटों को ज्यादा आराम देने की बात थी। इंडिगो इसी को दिक्कतों के लिए कसूरवार मान रही थी। नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि तीन दिनों में सेवाएं पूरी तरह बहाल होने की उम्मीद है।

फ्लाइट कैंसल पर Sorry...

असर शनिवार से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। डीजीसीए ने चार लोगों की जांच कमिटी बनाई है। जाइंट डीजी संजय कुमार ब्राहणे के नेतृत्व में कमिटी में डिप्टी डीजी अमित गुप्ता और दो अन्य अधिकारी शामिल हैं। यह कमिटी 15 दिनों में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। मंत्री ने कहा कि डीजीसीए के एफडीटीएल आदेश तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं। यह निर्णय पूरी तरह से यात्रियों, खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, मरीजों और अन्य लोगों के हित में लिया गया है। जो आवश्यक जरूरतों के लिए समय पर हवाई यात्रा पर निर्भर हैं।

डीजीसीए का आया आदेश
मंत्रालय और डीजीसीए ने इंडिगो को आदेश दिया है कि वह यात्रियों को फ्लाइट कैंसल या डिले होने की रीयल टाइम जानकारी अपडेट करें। ताकि प्रभावित यात्री घर बैठे अपनी फ्लाइट का स्टेटस जान सकें। एयरपोर्ट पर न आएं। लंबी देरी के कारण फंसे हुए यात्रियों के लिए एयरलाइंस की ओर से सीधे होटल में ठहरने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घंटे सातों दिन के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। जहां लोग 011-24610843, 011-24693963, 096503-91859 इन नंबरों पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं।

पैनी-स्टॉक | **Integrated Industries**

पैनी-स्टॉक Integrated Industries ने 5 साल में ₹1 लाख को करीब ₹5.96 करोड़ में बदला — निवेशकों की किस्मत बदल गई

नई दिल्ली | नई दिल्ली, 5 दिसंबर 2025 — शेयर बाजार में निवेशकों के लिए एक बार फिर “मल्टीबैगर” स्टॉक की चमक दिखाई दी है। Integrated Industries के शेयर ने पिछले पांच सालों में लगभग 59,500% तेजी दी है — यानी अगर किसी निवेशक ने दिसंबर 2020 में इस स्टॉक में ₹1लाख निवेश किया होता, तो आज उसकी वैल्यू करीब ₹5.96करोड़ हो चुकी होती।

इस तेजी का एक बड़े हिस्से के पीछे कंपनी द्वारा 1 सितंबर 2024 को किए गए स्टॉक स्प्लिट (₹10 से ₹1) तथा अप्रैल 2024 में 1:1 बोनस शेयर जारी करना है, जिससे निवेशकों को अतिरिक्त लाभ मिला।

हालाँकि, इस शेयर ने हाल के समय में उतार-चढ़ाव भी दिखाए हैं — 2025 में वर्ष-भर में यह लगभग 18% गिरा, लेकिन पिछले 6 महीनों में 19% उछाल आया और हाल के पाँच ट्रेडिंग सत्रों में 11% बढ़त दर्ज हुई।

Financials की बात करें, तो कंपनी ने सितंबर 2025 तिमाही में नेट प्रॉफिट में 108% वृद्धि दिखायी है — ₹14.40करोड़ से बढ़कर ₹29.88करोड़ हो गया। ऑपरेशनल रेवेन्यू 54% बढ़कर ₹286.46करोड़ रहा। इस आधार पर कंपनी अपनी प्रोसेस्ड फूड और अन्य प्रोडक्ट्स में विस्तार कर रही है, जिससे भविष्य में निवेशकों के लिए और अवसर बन सकते हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि यह सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही समय पर, धैर्यपूर्वक और लंबे अंतराल के लिए किये गए निवेश से शेयर बाजार में भारी रिटर्न हासिल किया जा सकता है — लेकिन इसके लिए स्टॉक चयन सही होना चाहिए और जोखिम की समझ भी जरूरी है।

1441% की गगनचुंबी उछाल — Rama Steel Tubes ने निवेशकों को कराया मालामाल”

मुंबई, 5 दिसंबर 2025 — छोटे-शेयर यानी “पेनी स्टॉक” के रूप में जानी जाने वाली Rama Steel Tubes ने पिछले पाँच वर्षों में ऐसा रिटर्न दिया है कि निवेशक दंग रह गए। कंपनी के शेयर दिसंबर 2020 में लगभग ₹ 0.64 थे, जो अब 5 दिसंबर 2025 को ₹ 9.86 तक पहुँच गए — यानि लगभग 1441 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि।

बोनस शेयर से मिली बड़ी सौगात
इस धमाकेदार उछाल में कंपनी द्वारा दिया गया बोनस शेयर बड़ा कारक रहा है। कंपनी ने जनवरी 2023 में 4:1 और मार्च 2024 में 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए। यानी, हर एक शेयर पर क्रमशः 4 व 2 बोनस शेयर मिले। इससे निवेशकों की हिस्सेदारी कई गुना बढ़ गई। ज़रूरी हो कि हम यह समझें कि बोनस शेयर मिलने से शेयर की संख्या बढ़ती है, लेकिन कुल पूंजी तय रहती है; रिटर्न इसलिए बढ़ना सामान्यतः तभी संभव होता है जब कंपनी का कारोबार या बाजार में मांग अच्छी हो। शेयर स्प्लिट और मल्टीबैगर बनने की कहानी

इतना ही नहीं, कंपनी ने 2016 में एक बार और 2022 में एक बार शेयर स्प्लिट भी किया — पहले 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 5-5 रुपये के शेयरों में तोड़ा गया, बाद में 5 रुपये वाले शेयर को 1 रुपये वाले 5 शेयरों में विभाजित किया गया। इस तरह स्प्लिट + बोनस ने शेयरधारकों की संख्या और हिस्सेदारी समेत “मल्टीबैगर” रिटर्न की नींव रख दी।

लेकिन... सतर्कता ज़रूरी..हालाँकि 5 साल में शानदार उछाल हुआ है, लेकिन कंपनी का स्टॉक हाल के महीनों में दबाव में भी रहा है। बीते 6 महीनों में शेयर लगभग 25 प्रतिशत नीचे आए हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार 1 साल में करीब 26 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल चुकी है।

विश्लेषक कहते हैं कि ऐसी तेज रफ्तार वाले “पेनी-स्टॉक” में उतार-चढ़ाव सामान्य है। इसलिए जो निवेशक अब इसमें कदम रखने की सोच रहे हैं, उन्हें कंपनी के फंडामेंटल्स, मार्केट ट्रेंड्स और व्यावसायिक विकास को ध्यान से समझना चाहिए — सिर्फ बोनस या स्प्लिट देखकर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है।

पाकिस्तान को बचाने फिर सामने आया सऊदी अरब, आर्थिक तंगी के बीच दिया अरबों डॉलर का सहारा, किया बड़ा ऐलान

इस्लामाबाद | आर्थिक स्तर पर मुश्किल का सामना कर रहे पाकिस्तान को उबारने के लिए सऊदी अरब एक बार फिर सामने आया है। सऊदी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) में रखे अपने 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट की मैच्योरिटी एक साल के लिए बढ़ा दी है। इससे चल रही लिक्विडिटी की चुनौतियों के बीच देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत करने में मदद मिली है।

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, सऊदी अरब के इस फैसले से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सऊदी के कदम के बाद उम्मीद जताई है कि यह देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मददगार साबित होगा।

दिसंबर 2026 तक के लिए राहत

सऊदी अरब ने फंड फॉर डेवलपमेंट (SFD) के माध्यम से पाकिस्तान को यह राहत दी है। यह सुविधा 2021 से जारी है और पाकिस्तान की मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता को सहारा देने के लिए इसे बार-बार बढ़ाया गया है। बैंक में जमा यह रकम मूल रूप से 8 दिसंबर, 2025 को परिपक्व होनी थी लेकिन अब दिसंबर 2026 तक SBP के पास रहेगी।

SBP ने अपने बयान में कहा है कि सऊदी का फैसला पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में मदद करेगा और देश के आर्थिक विकास और प्रगति में योगदान देगा। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि इससे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा कर सकेगा।

पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार

पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार इस साल 30 नवंबर तक 19.59 अरब डॉलर था। इसमें 14.57 अरब डॉलर केंद्रीय बैंक (SBP) के पास और 5.01 अरब डॉलर वाणिज्यिक बैंकों के पास थे। SBP के भंडार में हालिया समय में थोड़ी वृद्धि हुई है।

एक्सपर्ट का कहना है कि मौजूदा हालात में सऊदी अरब का जमा राशि का विस्तार पाकिस्तान को बड़ी वित्तीय राहत है। इससे वित्तीय सुधारों, ऋण प्रबंधन और IMF कर्ज के पुनर्गठन के लिए समय मिला है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मदद है।

WORLD NEWS | चीन की बड़ी चाल का खुलासा

चीन की बड़ी चाल का खुलासा, भारतीय सीमा के पास खड़ा किया आर्मी नेटवर्क, सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आया सच!

बीजिंग: चीन की सेना भारत के बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर निर्माण कर रही है। चीनी आर्मी तिब्बती पठार पर नए बड़े एयरफील्ड और दूसरी सुविधाएं तैयार कर रही है। इससे उसकी पहुंच हिमालय के ऊपर मुश्किल पश्चिमी सीमा तक बढ़ जाती है। चीन तिब्बत के पठार पर ना सिर्फ सैन्य बल्कि नागरिक उपयोग वाली सुविधाओं का भी नेटवर्क खड़ा कर रहा है। इससे युद्ध या संघर्ष जैसी स्थिति में चीनी सेना की पहुंच यहां आसानी से हो सकेगी।

वॉल स्ट्रीट जनरल (WSJ) ने अपनी रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये खुलासा किया है। WSJ ने सैटेलाइट इमेज के आधार पर बताया है कि ल्हुंजे, बुरंग और टिंगरी में तीन नई डुअल यूज फैसिलिटी बन रही हैं। इनमें कम से कम 72 एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर खड़े होने की सुविधा होगी। यह क्षेत्र में चीन की सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ाता है।

क्या है तस्वीरों में

द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ब्लैकस्काई नाम के एक रियल-टाइम स्पेस-आधारित इंटेलिजेंस कंपनी की 100 से अधिक सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है। यह कंपनी AI का उपयोग करके विमानों और अन्य प्रणालियों का पता लगाती है। 16 स्थानों की तस्वीरों में चीनी सेना के बढ़ते फुटप्रिंट के स्पष्ट प्रमाण दिखाई देते हैं।

इन तस्वीरों में एयरफील्ड एप्रन विभिन्न प्रकार के सैन्य विमान देखे जा सकते हैं। इनमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और टोही और हमलावर ड्रोन शामिल हैं। यह बुनियादी ढांचा ना सिर्फ भारत के खिलाफ चीन की स्थिति मजबूत करता है बल्कि तिब्बत में शासन को मजबूती से चलाने में बीजिंग की नियंत्रण क्षमता को भी बढ़ाता है।

चीन का नया निर्माण

भारत की सीमा के पास चीन की ये नई फैसिलिटी समुद्र तल से 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है कि रनवे ठंड से फटे नहीं। यह काम चीनी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी चाइना एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप कर रहा है।

चीनी अधिकारियों का कहना है इन हवाई अड्डों का निर्माण दूरदराज के इलाकों में लोगों को कनेक्टिविटी के लिए है। चीनी ये तर्क अपने सैन्य ढांचे पर पर्दा ढालने के लिए कर रहे हैं। तस्वीरों से साफ है ये सुविधाएं सैन्य अभियानों के लिए हैं। इनमें सैन्य विमानों के लिए मजबूत आश्रय इसका उदाहरण है।

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पस्त करने वाले S-400 एयर डिफेंस की बढ़ेगी ताकत, रूसी कंपनी का बड़ा ऐलान, भारत होगा खुश

मॉस्को | रूस के लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने हालिया समय में लगातार ध्यान खींचा है। रूस के इस सिस्टम का भारत भी इस्तेमाल कर रहा है। रूस इस सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन में कॉम्बैट ऑपरेशन में कर रहा है। वहीं भारत के लिए S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय एयर कैंपेन में अहम भूमिका निभाई थी। अब यह सिस्टम और ज्यादा प्रभावशाली होने जा रहा है। इस सिस्टम का बेहतर होना भारत के लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि भारतीय सेना को इससे अपनी हवाई सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी।

S-400 बनाने वाली कंपनी अलमाज-एंटे ग्रुप के सीईओ यान नोविकोव ने बताया कि यह सिस्टम युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुका है। कोई भी विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि S-400 की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। S-400 'ट्रायम्फ' ने ऐसी नई खूबियां हासिल की हैं, जो आमतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि इसे बेहतर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में S-400 और ज्यादा प्रभावशाली रूप में दिखेगा। S-400 का विकास

यान नोविकोव ने कहा कि S-400 की मारक क्षमता और अलग-अलग तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की खूबी इसे सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है। एस-400 साल 2007 में सेवा में आया था लेकिन इसे रूस में S-400 का बड़े पैमाने पर उत्पादन साल 2000 में क्रेमलिन की ओर से रूसी सतह से हवा में लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। इसमें एक बड़ा सुधार 40N6 लॉन्ग रेंज मिसाइल का एकीकरण था, जो 2018 में हुआ। इसके बाद भी इसमें कई बदलाव किए गए और आज भी इसे बेहतर करने का काम जारी है। मार करने वाली मिसाइलों की इंडस्ट्री में बड़े निवेश से संभव हुआ है। उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से तीन बड़ी नई सुविधाएं बनाई गईं। इनमें ओबुखोव प्लांट का एक नया विंग, किरोव में एविटेक प्लांट और निजनी नोवगोरोड में एनएमपी प्लांट शामिल हैं। इन सभी फैसिलिटी पर लगातार काम चल रहा है।

पुतिन का भारत दौरा

S-400 के बारे में इसकी कंपनी अलमाज-एंटे ने ये जानकारी ऐसे समय दी है, जब रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन गुरुवार को दिल्ली आए हैं। शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे भारतीय अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं।

इजरायल ने 2026 के रक्षा बजट में की भारी बढ़ोतरी,

गाजा युद्ध रुकने के बावजूद बढ़ाया खर्च, क्या नई लड़ाई का डर!

● **शहर का नाम :** तेल अवीव: इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की कैबिनेट ने अगले साल यानी 2026 का बजट पास कर दिया है। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी रकम रखी गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शुक्रवार को बताया है कि डिफेंस के लिए 112 बिलियन शेकेल (इजरायली करेंसी) रखा गया है। यह इजरायल सरकार की अपनी सेना और हथियारों पर खर्च बढ़ाने के इरादे को दिखाता है। इससे आने वाले वक्त में नई लड़ाई का अंदेशा पैदा होता है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली कैबिनेट के 2026 के लिए मंजूर किए गए बजट में रक्षा पर 112 अरब शेकेल (35 अरब डॉलर) का प्रावधान है, जो पहले के 90 अरब शेकेल के प्रस्ताव से काफी ज्यादा है। इस बजट को अब संसद में वोटिंग के लिए रखा जाएगा। हालांकि सरकार में मतभेदों के चलते इसे मंजूरी दिलाना नेतन्याहू के लिए आसान नहीं होगा। अगर बजट मार्च तक पास नहीं होता है तो चुनाव कराने पड़ेंगे।

इजरायल में अंदरुनी कलह

इजरायली कैबिनेट का रक्षा बजट पर यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब इजरायल की सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टियों और अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी पार्टियों में गाजा युद्धविराम पर मतभेद चल रहे हैं। ये पार्टियां चाहती हैं कि यहूदी धार्मिक छात्रों को सेना की अनिवार्य सेवा से छूट मिले। इस पर फिलहाल सरकार सहमत होती नजर नहीं आ रही है।

इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) के बजट में बढ़ोतरी की वजह स्पष्ट है। उन्होंने कहा, 'हम IDF को मजबूत करने और सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं। हम रिजर्व सैनिकों पर बोझ कम करेंगे ताकि हर मोर्चे पर इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। '

वित्त मंत्री ने क्या कहा है

इजरायल के लिए दो साल तक चला गाजा युद्ध काफी महंगा साबित हुआ है। बीते साल 2024 में फिलिस्तीनी गुट हमास और लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के साथ सैन्य संघर्षों पर इजरायल ने 31 अरब डॉलर खर्च किए थे। फिलहाल इजरायल का दोनों के साथ युद्धविराम समझौता हो चुका है।

इजरायली वित्त मंत्री बेजल स्मोट्रिच की ओर से कहा गया है कि 2026 के लिए रक्षा बजट 2023 की तुलना में 47 अरब शेकेल ज़्यादा है। गाजा में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले 2023 में रक्षा बजट कम था। हम इस साल सेना को मजबूत करने के लिए भारी बजट आवंटित कर रहे हैं।

स्मोट्रिच ने कहा कि यह बजट इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। रक्षा पर ज्यादा खर्च के पीछे मकसद अपनी सेना को आधुनिक बनाने और सीमाओं को सुरक्षित रखने पर जोर है।

जिहादी असीम मुनीर के हाथ में आया पाकिस्तान का परमाणु बटन, CDF बनते ही कैसे बढ़ी ताकत, क्या भारत के लिए बन सकते हैं खतरा!

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में एक हफ्ते चली अटकलों के बाद आखिरकार पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स (सीडीएफ) की नियुक्ति हो गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने असीम मुनीर को पांच साल के लिए सीडीएफ बनाया है। पाकिस्तान में विपक्ष के विरोध के बीच किए गए संविधान संशोधन के जरिए इस पद को बनाया गया है। इससे उनकी ताकत को कई गुना बढ़ गई है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अब परमाणु हथियारों का कंट्रोल मुनीर के पास आ गया है। यह कहीं ना कहीं क्षेत्र के दूसरे देशों खासतौर से भारत के लिए चिंता का सबब हो सकता है।

जिहादी असीम मुनीर के हाथ में आया पाकिस्तान का परमाणु बटन

पाकिस्तान में CDF नया और बेहद ताकतवर पद है, जो तीनों सैन्य सेवाओं-थल सेना, नौसेना और वायु सेना का हेड होगा। असीम मुनीर अब आर्मी चीफ और CDF दोनों हैं। CDF तीनों सैन्य सेवाओं के साथ-साथ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की भी निगरानी करेगा। यह कमांड पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों का प्रबंधन करती है।

असीम मुनीर सबसे ताकतवर

CDF बनने के साथ ही असीम मुनीर देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। इस नए पद के साथ उन्हें राष्ट्रपति की तरह उनको किसी भी कानूनी मुकदमे से आजीवन छूट मिलेगी। यह भी संभावना है कि अगर मुनीर पांच साल बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से दोबारा नियुक्ति की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उनकी मांग को शायद ही नकारा जाएगा।

नंदिग्राम टाईम्स

Sat 6th, December 2025 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 220 | ● पृष्ठ 04 | ● RNI-MAHHIN/2016/69743 | ● www.nandigramtimes.com

नांदेड़ मनपा की प्रारूप मतदाता सूची पर 348 आपत्तियाँ; आधी से अधिक 'मोघम', दो प्रभागों में सिर्फ एक-एक हरकत

मनपा की प्रारूप मतदाता सूची पर 348 आपत्तियाँ;

नांदेड : आगामी महानगरपालिका चुनावों के लिए जारी प्रारूप मतदाता सूची पर कुल 348 आपत्तियाँ दर्ज हुई हैं। इनमें से आधी से अधिक आपत्तियाँ 'मोघम' (अस्पष्ट/अधूरी) श्रेणी में आने के कारण चुनाव विभाग इन्हें अदाखिलपात्र करने की तैयारी में है। केवल वही आपत्तियाँ विचारणीय होंगी जिनकी जांच संभव है।

राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2025 की मतदाता सूची को आधार मानकर 19 नवंबर को सभी 20 प्रभागों की प्रारूप सूची जारी की गई थी। पहले 27 नवंबर तक और बाद में बढ़ी हुई समयसीमा 3 दिसंबर तक नागरिकों को आपत्तियाँ दर्ज करने का अवसर दिया गया।

मतदाता नाम खोज सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, परंतु यह अंतिम दिनों में सक्रिय होने से नागरिकों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल सका।

सबसे कम आपत्तियाँ हनुमानगढ़ (प्रभाग 4) और उमर कॉलनी (प्रभाग 12) में केवल 1-1, जबकि इतवारा-मदीना नगर (14) में 2 और चौफाला/करबला (13) में 3 आपत्तियाँ मिलीं।

इसी बीच मनपा क्षेत्र में 7,586 दुबार मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें सूची में दो स्टार (*) चिह्न से दर्शाया जाएगा। ऐसे मतदाता मतदान केंद्र पर यह घोषणा-पत्र भरने के बाद ही वोट डाल सकेंगे कि उन्होंने अन्य स्थान पर मतदान नहीं किया है।

यह पूरी प्रक्रिया मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

NANDED NEWS | नांदेड के लिए 'CRRI' ट्रैफिक सर्वेक्षण को मंजूरी

सांसद डॉ. अजित गोपछड़े के प्रयास सफल; नांदेड के लिए 'CRRI' ट्रैफिक सर्वेक्षण को मंजूरी

नांदेड | नांदेड शहर की बढ़ती यातायात समस्या का वैज्ञानिक समाधान खोजने के लिए किए जा रहे प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। राज्यसभा सांसद डॉ. अजित गोपछड़े द्वारा एक वर्ष से किए जा रहे लगातार प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने नांदेड के लिए CRRI (सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा ट्रैफ़िक सर्वेक्षण कराने पर सकारात्मक निर्णय दिया है।

राज्यसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न क्रमांक 604 के उत्तर में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि नांदेड में विस्तृत ट्रैफ़िक सर्वेक्षण के लिए CSIR के अंतर्गत आने वाले CRRI को प्रस्ताव अप्रैल 2025 में भेजा गया था। नांदेड देश का एक प्रमुख सिख तीर्थ स्थल होने के कारण सर्वेक्षण शुल्क में छूट की मांग की गई थी। सर्वेक्षण शुल्क में आंशिक छूट मिलने के बाद शेष 82 लाख 60 हजार रुपये की रक़म नांदेड जिला नियोजन समिति से मंजूर कर महानगरपालिका को सहायता के रूप में देने का प्रस्ताव सांसद डॉ. गोपछड़े ने पालक मंत्री अतुल सावे की अध्यक्षता वाली बैठक में रखा है।

इस निर्णय से नगर निगम पर आर्थिक बोझ कम होगा और नांदेड शहर को यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अध्ययन का लाभ मिलेगा।

नांदेड़ में मंगलवार को जिल्हाधिकारी कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन

नांदेड़। 5 दिसंबर 2025
नांदेड़ जिले में सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आगामी मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 को जिल्हाधिकारी कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से ढाई बजे तक आयोजित किया जाएगा।

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले ने सभी सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों से अपील की है कि वे पेंशन अदालत के दिन अपनी समस्याओं और शिकायतों के साथ उपस्थित रहें और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस अवसर पर पेंशन से संबंधित सभी प्रश्नों का निवारण किया जाएगा।

यह पहल कर्मचारियों को उनके पेंशन संबंधी मुद्दों का शीघ्र समाधान प्रदान करने के लिए की जा रही है।

जिला परिषदों में नया आरक्षण तय होने की संभावना;

उम्मीदवारों की तैयारी पर विराम

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद महाराष्ट्र की 20 जिला परिषदों में आरक्षण प्रक्रिया दोबारा लागू होने की संभावना बढ़ गई है। नांदेड़ सहित कई जिलों में राजनीतिक आरक्षण 50% की सीमा से अधिक होने के कारण अब पूरी प्रक्रिया पुनः संचालित किए जाने की स्थिति बन रही है।

इस संभावित निर्णय ने जिला परिषद चुनाव की तैयारी में जुटे कई इच्छुक नेताओं की रणनीति को झटका दिया है।
जिस 'मिनी मंत्रालय' में प्रवेश के लिए वे बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहे थे, वहां अब नए आरक्षण के कारण अनिश्चितता का माहौल बन गया है। उम्मीदवारों के सामने यह सवाल खड़ा है कि संशोधित आरक्षण किस वर्ग या समूह के लिए अनुकूल रहेगा और उनके राजनीतिक समीकरण किस दिशा में जाएंगे।

जिन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में 50 प्रतिशत सीमा पार हुई है, उनके चुनाव परिणाम सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होने वाली है, जिसके बाद चुनावी तस्वीर और आरक्षण व्यवस्था स्पष्ट होने की उम्मीद है।

राजनीतिक हलकों में इस बदलती स्थिति पर चर्चा तेज है और इच्छुक उम्मीदवार प्रतीक्षा की मुद्रा में हैं।

नांदेड़ : भारी बारिश और कर्ज की मार; मुर्तिजापुर में 20 वर्षीय किसान के बेटे ने की आत्महत्या

संवाददाता |

मुर्तिजापुर में किसान पुत्र की आत्महत्या: मुर्तिजापुर में एक किसान के 20 वर्षीय बेटे दीपक येरदावकर ने भारी बारिश, फसल की बर्बादी और कर्ज के कारण अपने खेत में एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि परिवार पर कर्ज का पहाड़, लगातार फसल की बर्बादी और मानसिक तनाव समेत इन सभी कारणों से युवक की जिंदगी हिल गई थी।

मुर्तिजापुर: भारी बारिश, लगातार फसल बर्बादी और कर्ज से तंग आकर यहां एक किसान के बेटे ने दो दिन पहले अपने खेत में एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले किसान के बेटे का नाम दीपक कुलदीप येरदावकर (20) है। शहर के सोनोरी रोड निवासी कुलदीप शंकरराव येरदावकर के छोटे बेटे ने खेत में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कुलदीप येरदावकर के पास आठ एकड़ ज़मीन है और बताया जाता है कि उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज़ लिया हुआ है। कर्ज़ के पहाड़ से कुलदीप पूरी तरह टूट चुके थे।

टि.सी.हरवली आहे

माझी रऊफ खाँ खुदरत खाँ पठाण या नावाची 7 वी ची टि.सी. हिमायतनगर ते नांदेड एस टी बस ने प्रवासात गहाळ झाली आहे. कोणास सापडल्यास खालील पत्यावर आणून द्यावी. आणून देणाऱ्यास योग्य ते बक्षिस देण्यात येईल.

संपर्क करें
रऊफ खाँ खुदरत खाँ पठाण,
रा.करंजी पोस्ट सरसम
ता. हिमायतनगर, जि. नांदेड.
मो. नंबर (+919922735787)
Client email id.

टीईटी परिणाम पर शिक्षक संघ का मोर्चा,

नांदेड़। 5 दिसंबर 2025
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक समन्वय समिति ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) परिणाम के संदर्भ में दिए गए निर्णय के खिलाफ आज जिल्हाधिकारी कार्यालय पर मुक मोर्चा निकाला।

संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। मोर्चे के दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों का निवेदन अपर जिल्हाधिकारी को सौंपा।

मांगपत्र में शिक्षक संघ ने स्पष्ट किया कि टीईटी परिणाम से प्रभावित उम्मीदवारों के हित में पुनर्विचार याचिका आवश्यक है और **उन्होंने सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की। जिल्हाधिकारी कार्यालय ने मोर्चे के दौरान** शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुना और आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

नांदेड़ के शिवनगर में घरफोड़ चोरी, 1 लाख 70 हजार का माल पार —

एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज

नांदेड़ शहर के शिवनगर इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। घटना 3 दिसंबर की सुबह साढ़े छह बजे से लेकर 4 दिसंबर की सुबह लगभग पाँच बजे के बीच की बताई जा रही है। इस दौरान अज्ञात चोर ने बंद पड़े घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखे सोने-चांदी के आभूषण तथा पीतल की देवी-देवताओं की मूर्तियाँ चुरा लीं। चोरी गए सामान की कुल कीमत लगभग 1 लाख 70 हजार रुपये आंकी गई है।

इस मामले में पीड़ित यादव कोंडेवाड की शिकायत के आधार पर आज दोपहर नांदेड़ के एयरपोर्ट पुलिस थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों की गतिविधियों की पड़ताल में जुटी हुई है।

स्वाधिकारी नंदिग्राम टाईम्स (नांदेड़) के मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक शेख जहूर शेख अहेमद द्वारा सहारा डिजाइनिंग एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वाजेगांव, ता. व जि. नांदेड़ में मुद्रित तथा दैनिक नंदिग्राम टाईम्स, मुल्लाह मार्केट, खवी बिल्डिंग, नगरेश्वर मंदिर, नांदेड़-431604 (महाराष्ट्र) के कार्यालय से प्रकाशित। RNI-MAHHIN/2016/69743 मोबाइल संपर्क: 9921100075 | Email: ntinfodesk@gmail.com (वाद-विवाद हेतु न्यायक्षेत्र: नांदेड़ न्याय कक्षा में।)